



रामनवमी के पावन पर्व पर अद्वितीय घटना के रूप में, रविवार सुबह 11:58 बजे दिव्य सूर्यप्रकाश ने रामलला के माथे को धीरे-धीरे स्पर्श किया, जिससे सूर्य अभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत हुई। यह मनमोहक दृश्य चार मिनटों तक चला। यह भगवान राम के भक्तों के लिए एक असाधारण क्षण था। इस अलौकिक क्षण में भगवान के प्राकट्य की आरती हुई। काउन्सिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटरडिप्लोमेटिक रिसर्च सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार, तिलक का निर्धारित आकार 58 मिमी है। उन्होंने बताया कि माथे के केन्द्र पर तिलक की सटीक अवधि लगभग तीन से डेढ़ मिनट थी, जिसमें दो मिनट तक पूरी रोशनी रही। सूर्य तिलक की तैयारियों के लिए इसरो व सी.बी.आर.आई. के वैज्ञानिकों की टीम ने अयोध्या में डेरा डाल रखा था। रविवार की शाम सरयू तट पर दो लाख दीपों की अद्भुत छटा भी देखने को मिली।

अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया

दिन में 12 बजे वैज्ञानिकों ने भगवान सूर्य की किरणों से तिलक रामलला का अभिषेक कराया

अयोध्या, 6 अप्रैल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान रामलला का जन्मोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया गया। "भाए प्रकट कृपाला, दीनदयाला कौशल्या हितकारी। हरषित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी।" चौपाई के साथ राम मंदिर में श्रीरामलला का प्रतीकात्मक रूप से जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ठीक बारह बजे दोपहर रामलला को दूध से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए गए।

वैज्ञानिकों द्वारा भगवान सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक, अभिषेक कराया गया। प्रतीकात्मक रूप से भगवान श्रीराम ने जन्म लिया। भगवान सूर्य ने रामलला के ललाट पर लगभग चार मिनट तक

- रामनवमी मेले को दस सैक्टरों में बांटा गया। पूरी रामजन्म भूमि में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। जिनकी तैयारी एक सप्ताह से चल रही थी।
- श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व्यास द्वारा बड़ी संख्या में एलईडी स्क्रीन लगाई गईं, जिन पर श्री रामलला का जन्मोत्सव सीधे दिखाया गया। रामलला को 56 प्रकार के भोग भी अर्पित किये गये।

तिलक किया।

रामलला के जन्म पर अयोध्या के मंदिरों में बधाई व सोहर गीत शुरू हो गये। जगह-जगह पटाखे चलने लगे। घंटे, घड़ियालों व शंख की करतल ध्वनि के बीच श्रीरामलला प्रकट हुए। उसके बाद पूरा वातावरण भगवान श्रीराम के नाम से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर बधाई, सोहर गीत, प्रसाद वितरण आदि का

सिलसिला जारी रहा। रामजन्म के लिए पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजायी गयी है। किन्नर समुदाय के लोग मठ-मंदिरों में जाकर महंतों से नेम, न्यौछावर मांग रहे हैं। जिलाधिकारी चन्द्रविजय सिंह ने बताया कि रामलला के जन्मोत्सव अर्थात् रामनवमी मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने रामलला के जन्मोत्सव के साथ-साथ विभिन्न मंदिरों में

जाकर दर्शन-पूजन किया। श्रीरामजन्मभूमि क्षेत्र में भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जन्मोत्सव की तैयारियां विगत एक सप्ताह से युद्ध स्तर पर चल रही थीं। इस अवसर पर पंजीरी, कुट्टू व सिंघाड़े का आटा व रामदाना का भोग लगाया गया था जो श्रद्धालुओं में बांटा गया।

उन्होंने बताया कि जन्मभूमि में दर्शनार्थियों सहित सभी को प्रसाद वितरण किया गया। श्रीरामजन्मभूमि पर विराजमान रामलला के मंदिर के अलावा छोटे-बड़े करीब 121 मंदिरों में शहर एवं नगर निगम क्षेत्र परिधि के बाहर श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट न्यास द्वारा काफी मात्रा में एलईडी स्क्रीन लगायी गयीं जिनमें रामलला का जन्मोत्सव सीधे दिखाया गया।

अमेरिका ने दक्षिण सूडान के सारे वीजा रद्द किये

वाशिंगटन, 6 अप्रैल। अमेरिका ने दक्षिण सूडान को पासपोर्ट धारकों के सभी वीजा रद्द कर दिये हैं तथा नए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने शनिवार को एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई दक्षिण सूडान की संक्रमणकालीन सरकार द्वारा अपने निर्वासित नागरिकों की वापसी को समय पर स्वीकार करने में विफल रहने के बाद की गई है।

उन्होंने कहा कि जब दक्षिण सूडान पूर्ण सहयोग देगा

- अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि यह कार्यवाही दक्षिण सूडान द्वारा निर्वासित नागरिकों की वापसी स्वीकार नहीं करने के कारण की गई।

तो उनका देश इन कार्यों को समीक्षा करने के लिए तैयार होगा।

यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी विशिष्ट देश के सभी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा प्रतिबंध लगाया है। डॉनल्ड ट्रम्प के जनवरी 20 को पदभार संभालने के बाद से अब तक का पहला ऐसा मामला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में कई कड़े फैसले लिए हैं, जिनमें इमिग्रेशन नीति में बदलाव और अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर सैन्य तैनाती शामिल है।

मोदी ने भारत के पहले सी-लिफ्ट ब्रिज "पंबन पुल" का उद्घाटन किया

रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल परिवहन व सांस्कृतिक प्रतीक बनेगा

- पंबन ब्रिज के अलावा, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कई परिवर्तनकारी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया।

ब्रिज ने केवल परिवहन को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग के चमत्कार को वैश्विक मंच पर पहुंचायेगा। इसके साथ ही यह एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक और सांस्कृतिक प्रतीक दोनों के रूप में कार्य करेगा। रामायण के अनुसार, जहाजों का सुगम मार्ग तथा निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित होता है। नए पंबन ब्रिज के उद्घाटन के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम-तांबरम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे पवित्र शहर रामेश्वरम और चेन्नई के तांबरम के बीच रेल संपर्क बढ़ेगा।

नए पंबन ब्रिज के अलावा, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कई परिवर्तनकारी सड़क

परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। ज्ञातव्य है कि दक्षिण रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने 27 दिसंबर, 2024 को बताया था कि यह पंबन ब्रिज संचालन के लिए 100 प्रतिशत तैयार है। उन्होंने चेन्नई से आए मॉडिया दल के एक समूह को वॉटिकल लिफ्ट स्पैन को भी दिखाया था। इस दौरान मॉडियाकर्मियों को मंडपम रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को भी दिखाया था। जंग के संकेतों सहित सभी मुद्दों को संबोधित करने के बाद नए पंबन ब्रिज को पहले रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की मंजूरी मिल गई थी।

उन्होंने बताया था कि पुराने पुल की तरह, नया पुल भी 100 साल तक टिकेगा और इस पर 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी।

राहुल गांधी सोमवार को बेगूसराय जायेंगे

नयी दिल्ली, 06 अप्रैल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह सोमवार को बिहार के बेगूसराय में युवाओं से मिलेंगे और पलायन तथा बेरोजगारी के विरुद्ध उनके संघर्ष में

- वे पयालन व बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं के आंदोलन में भाग लेंगे।

शामिल होंगे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि वे बेगूसराय में हो रहे इस आंदोलन में सफेद टी-शर्ट पहनकर शामिल हों और सत्कार पर, पलायन रोकने और उन्हें नौकरी देने की अपनी मांगों के लिए दबाव बनाएं।

गांधी ने कहा, "बिहार के युवा साथियों, मैं सात अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूँ, 'पलायन रोको, नौकरी दो' यात्रा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री विश्व स्वास्थ्य दिवस पर "निरामय राजस्थान" का शुभारम्भ करेंगे

इस अभियान में ईट राइट, मिशन लिवर, स्माइल आदि कार्यक्रम शुरु होंगे

जयपुर, 6 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार (7 अप्रैल) को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में निरामय राजस्थान अभियान सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारम्भ करेंगे। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ईट राइट राजस्थान अभियान, मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल अभियान एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का भी शुभारंभ करेंगे।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अवसर पर 26 करोड़ रुपये की लागत के, स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं से जुड़े कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे।

इसके साथ ही आयुष्मान योजना का मोबाइल ऐप व आयुष पैकेज, एआई आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम, लॉनिंग मैनेजमेंट सिस्टम, 29 स्तनपान प्रबंधन इकाइयों (एलएमयू) व 50 चिकित्सा संस्थानों में हीमोडायलिसिस

वार्ड का भी शुभारंभ किया जाएगा। शर्मा इस अवसर पर 26 करोड़ की लागत की स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट रिकल सेंटर, जेके लॉन अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जयपुर में सेंट्रल ऑफ एमसलैस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में गर्ल्स हॉस्टल तथा प्रिप्रोडिक्टिव मेडिसिन व सर्जरी विभाग का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 22 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन ने अमेरिका की नई मनमानी "टैरिफ" नीति के खिलाफ डब्ल्यू.टी.ओ. में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई

हालांकि, यह सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में डब्ल्यू.टी.ओ. (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन) में शिकायत दर्ज कराना बेमामने प्रसंग है, पर, फिर चीन इस रास्ते पर क्यों आगे बढ़ा है?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अप्रैल। वाशिंगटन की व्यापार नीति को साहसिक चुनौती देते हुए चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (डब्ल्यू.टी.ओ.) का रूख किया है और उस बहुपक्षीय सिस्टम के अधिकारों का हवाला दिया है, जिसे पुराना मानकर खारिज कर दिया गया था। बीजिंग की शिकायत, जिसकी पुष्टि इसके वाणिज्य मंत्रालय ने की है, अमेरिका के "रेसिप्रोकल टैरिफ" नीति के ऐसे उपयोग को दर्शाती है, जिसने न केवल चीन के बल्कि अन्य देशों के अमेरिका निर्यात को बाधित किया है। यह कदम एक सोचा समझा निर्णय है, जो दर्शाता है कि चीन न केवल कूटनीति से बल्कि कानूनन भी अमेरिका के साथ मुकाबले के लिए तैयार है।

इस नए विवाद के मूल में एक ही प्रश्न है कि अगर डब्ल्यू.टी.ओ. ने चीन के पक्ष में फैसला दिया तो क्या होगा? क्या अमेरिका इसे मानेगा।

औपचारिकरूप से, वाशिंगटन के खिलाफ निर्णय चीन को डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा अनुमानित क्षति के बराबर मुआवजे की मांग करने का या प्रतिशोषी टैरिफ लागू करने का अधिकार देगा। लेकिन प्रवर्तन की प्रक्रिया अब पहले जैसी सरल नहीं रही। दिसंबर 2019 से डब्ल्यू.टी.ओ. अपैलेंट बॉडी, जो

- अगर डब्ल्यू.टी.ओ. किसी शिकायत को सही स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुना भी देता है तो आगे कुछ और कार्यवाही नहीं कर सकता, क्योंकि, डब्ल्यू.टी.ओ. की अपीलेंट संस्था, जो आर्थिक दण्ड, मुआवजा आदि के निर्णय को फाइनल करती है, पालना करवाती है, कई वर्षों से निष्पत्ती पड़ी है, क्योंकि अमेरिका नये जज की नियुक्ति नहीं होने दे रहा।

- अतः किसी भी देश की जायज शिकायत भी प्रशासनिक कुएं में जाकर जलमग्न हो जाती है।

- चीन का शायद मानना है कि आज की जटिल वाणिज्य व व्यापारिक परिस्थिति में, एक तटस्थ व मजबूत संस्था की जरूरत सभी महसूस कर रहे हैं। अतः डब्ल्यू.टी.ओ. का पुर्नगठन तो होना ही है।

- चीन द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. में दर्ज शिकायत ने इतना तो कर ही दिया कि चीन को आर्थिक रूप से उभरते देशों की सहानुभूति तो मिल गई है और इन देशों में चीन की साख जमी है।

- यह दोनों बातें, डब्ल्यू.टी.ओ. के पुर्नगठन में, या इसकी जगह कोई नई संस्था बनाने समय, चीन की भूमिका को और असरदार बना देंगी।

व्यापार विवादों में अंतिम निर्णायक होता है, लगभग पंगु सी है क्योंकि अमेरिका द्वारा नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध किया गया है। वाशिंगटन लंबे

समय से चिंता व्यक्त कर रहा है कि यह निकाय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देता है, नियमों की अत्यधिक व्याख्या करता है और राष्ट्रीय

संप्रभुता को कमजोर करता है। इस संस्थागत गतिरोध ने एक प्रक्रिया संबंधी स्वामी उत्पन्न की है, जिसे "शून्य में अपील" के रूप में जाना जाता है। डब्ल्यू.टी.ओ. प्रणाली में, हारने वाली पार्टी पैनल के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकती है। लेकिन चूँकि अपीलीय निकाय में कोई न्यायाधीश नहीं हैं, इसलिए ऐसी कोई भी अपील कानूनी शून्य में गायब हो जाती है, जिससे मामला अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाता है और निर्णय लागू नहीं किया जा सकता।

परिणामस्वरूप विवाद स्थायी और अनसुलझा रह जाता है।

कई देशों, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ने पहले ही इस रणनीति का उपयोग किया है। एक हालिया उदाहरण भारत के आई.सी.टी. मामले (डीएस584) का है वर्ष 2019 में, यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान ने भारत के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों, जैसे मोबाइल फोन और उनके घटकों पर टैरिफ लगाने को चुनौती दी। इन देशों ने तर्क दिया कि भारत के टैरिफ डब्ल्यू.टी.ओ. के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत उसकी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं, जो सूचीबद्ध उत्पादों पर ज़ीरो शुल्क लगाने का आदेश देता है। भारत ने जवाब दिया कि कुछ वस्तुएं या तो नहीं थी या समझौते के तहत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)